



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷிண் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினகரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बंगलूरु से एक साथ प्रकाशित



5 गोमांस फैंकने का धंधा बंद होना चाहिए, अन्यथा बदले की कार्रवाई हो सकती है

6 आपातकाल : आधी रात जब छिन गए थे जनता के सारे अधिकार

7 मोदी की पार्टी में शामिल होने का मेरा कोई संकेत नहीं : थरू

फ़र्स्ट टेक

सीडीएस चौहान तीनों सेनाओं को आदेश जारी करने हेतु अधिकृत

नई दिल्ली/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान को संयुक्त निर्देश एवं संयुक्त आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया है। यह उस पुरानी प्रणाली में किया गया परिवर्तन है, जिसमें दो या अधिक सेनाओं से संबंधित निर्देश/आदेश प्रत्येक सेना द्वारा अलग-अलग जारी किए जाते थे। यह कदम सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्तता के लिए 'थिएटराइजेशन मॉडल' को लागू करने के सरकार के प्रयासों के बीच उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संयुक्त निर्देशों और संयुक्त आदेशों के 'अनुमोदन, प्रकाशन और क्रमांकन' पर पहला संयुक्त आदेश मंगलवार को जारी किया गया।

जापान ने पहली बार किया मिसाइल परीक्षण

टोक्यो/एपी। जापान ने अपने क्षेत्र में पहली बार मिसाइल परीक्षण किया है। देश की सेना ने मंगलवार को यह घोषणा की। जापान के उत्तरी मुख्य द्वीप होक्काइडो के 'शिजुनाई एंटी-एयर फायरिंग रेंज' में 'टाइप-88' मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो सतह से जहाज पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। अधिकारियों ने बताया कि 'ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स' की पहली 'आर्टिलरी ब्रिगेड' के अभ्यास में लगभग 300 सैनिक शामिल हुए, जिन्होंने होक्काइडो के दक्षिणी तट से लगभग 40 किलोमीटर दूर जहाज पर गोलीबारी की थी, जिसमें कोई भी चालक नहीं था। उन्होंने बताया कि अधिकारी अभी परीक्षण के परिणामों की जांच कर रहे हैं। जापान, चीन के प्रतिरोध के लिए जवाबी हमला करने की क्षमता हासिल करने के लिए अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा रहा है।

इंडोनेशिया में आधे टन से अधिक मादक पदार्थ जप्त, 285 लोग गिरफ्तार

जकार्ता (इंडोनेशिया)/एपी। इंडोनेशिया में दो महीने की कार्रवाई के दौरान 29 महिलाओं और सात विदेशियों समेत 285 लोगों को मादक पदार्थों की तस्करी के संदेह में गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से आधे टन से अधिक मादक पदार्थ जप्त किया गया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। इंडोनेशिया में मादक पदार्थों से संबंधित सख्त कानून हैं तथा दोषी तस्करों को कभी-कभी गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है। इसके बावजूद यह दक्षिण पूर्व एशिया में मादक पदार्थों की तस्करी का एक प्रमुख केंद्र है।

25-06-2025 सुबोद 6:38 बजे 26-06-2025 सुबोद 5:44 बजे

BSE 82,055.11 (+158.32) NSE 25,044.35 (+72.45)

सोना 10,216 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम चांदी 120,000 रु. प्रति किलो

निशान मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



केलशा मण्डेला, मो. 9828233434

सभी मगन हैं

व्यापारी बस सोच रहा है, कैसे आए जी भर नोट। ढूँढ रहे हैं सभी किकेटर, आइपीएल में लम्बे शाट। पार्टी वाले नेतागण सब, पकड़ रहे हैं वोटर वोट। आम आदमी राम भरोसे, गुमसुम बैठा खा कर चोट।।

आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड से बचें : एनएसए डोमाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बीजिंग/भाषा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड अपनाने से बचने का आह्वान किया और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्यों से सीमा पार आतंकवाद के अपराधियों, आतंकवादी और वित्तपोषकों को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया।

इसे व्यापक रूप से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग के रूप में देखा जा रहा है।

डोभाल ने बीजिंग में एससीओ के सुरक्षा परिषद सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।

एनएसए ने कहा कि भारत, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), अलकायदा, आईएसआईएस और इसके सहयोगी जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी



सीमापार आतंकवाद सहित आतंकवाद का कोई भी कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध है।

समूहों से लगातार खतरे को लेकर बेहद चिंतित है।

डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड को त्यागने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सीमापार आतंकवाद सहित आतंकवाद का कोई भी कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध है।

एनएसए ने एससीओ सदस्यों से सीमापार आतंकवादी कृत्यों के अपराधियों,

आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने तथा उन्हें न्याय के दायरे में लाने में मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पहलगांम आतंकवादी हमले के बाद नई दिल्ली ने आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और आतंकवादियों को भारत में हमले करने से रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया।

भारतीय वायुसेना को मार्च 2026 तक कम से कम छह तेजस विमान मिल जाएंगे एचएएल के प्रमुख डी के सुनील ने यह जानकारी दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बैंगलूरु/नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना को मार्च 2026 तक कम से कम आधा दर्जन हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस मिल जाएंगे। इन अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रही कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के प्रमुख ने यह जानकारी दी। एलसीए तेजस के एमके-1ए संस्करण की आपूर्ति में देरी का मामला वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह ने हाल ही में उठाया था, जिसके बाद यह बड़ा मुद्दा बन गया था। एचएएल के प्रमुख ने कहा है कि तेजस की आपूर्ति में हुई देरी के लिए जीई एयरोस्पेस द्वारा इंजन की आपूर्ति में विलंब जिम्मेवार है। एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) डी के सुनील ने कहा



कि यह देरी केवल अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस द्वारा समय पर एफ404 इंजन की आपूर्ति करने में असमर्थता के कारण हुई।

एचएएल प्रमुख ने 'पीटीआई वीडियो' के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि जीई एयरोस्पेस द्वारा चालू वित्त वर्ष में 12 इंजन की आपूर्ति किये जाने की उम्मीद है। इससे भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में आसानी होगी। उन्होंने कहा, "हर कंपनी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा होता (ही) है। दुर्भाग्य से, एलसीए मार्क-1ए के

■ जीई एयरोस्पेस से इंजन की आपूर्ति नहीं हुई है। जीई को 2023 में इंजन की आपूर्ति करनी थी। अब तक, केवल एक इंजन मिला है।

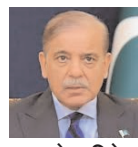
■ जीई की ओर से देरी शुरू में कोविड महामारी के दौरान उत्पादन में विलंब और उसके बाद कंपनी से कई वरिष्ठ इंजीनियरों के चले जाने के कारण हुई, जिससे आपूर्ति शृंखला में बाधा उत्पन्न हुई।

मामले में (भी ऐसा ही हुआ है), हमने विमान बना लिये हैं। आज की तारीख में, हमारे पास छह विमान तैयार हैं।" उन्होंने कहा, "लेकिन जीई एयरोस्पेस से इंजन की आपूर्ति नहीं हुई है। उसे (जीई को) 2023 में इंजन की आपूर्ति करनी थी। अब तक, हमें केवल एक इंजन मिला है।" जीई की ओर से देरी शुरू में कोविड महामारी के दौरान उत्पादन में विलंब और उसके बाद कंपनी से

पाकिस्तान सभी मंचों पर ईरान का समर्थन करेगा : प्रधानमंत्री शरीफ

इस्लामाबाद/भाषा।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को सभी मंचों पर ईरान का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई और सऊदी अरब तथा कतर के राजनयिकों के साथ पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे हालात पर चर्चा की। यहां एक सरकारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति के लिए खतरा बने बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई। प्रधानमंत्री शरीफ ने सभी मंचों पर ईरान का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई। इसके पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल-ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्धविराम की घोषणा की थी। आधिकारिक बयान के अनुसार, ईरानी नेता मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे हालात पर करीबी नजर रख रहा है। उन्होंने बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति बहाल करने के महत्व पर जोर दिया।



अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि हमारे समूह के बनाए ड्रोन ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में अग्रणी भूमिका निभायी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा।

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने मंगलवार को कहा कि उनके समूह द्वारा बनाए गए ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणालियों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में अग्रणी भूमिका निभाई थी। 'ऑपरेशन सिंदूर' पहलगांम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब के तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ शुरू किया गया था।

अपने समूह की वार्षिक आम बैठक में अदाणी ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर' हुआ और हमने कर दिखाया। 'अदाणी डिफेंस' द्वारा निर्मित हथियारों ने सटीक हमले किए, जबकि इसकी ड्रोन रोधी इकाइयों ने जवाबी खतरों से भारतीय संपत्तियों की रक्षा की। उन्होंने कहा, हमारे ड्रोन आसमान में नजर रखने वाली आंख के साथ-साथ हमले की तलवार भी बन गए हैं और हमारी



ड्रोन रोधी प्रणालियों ने हमारे बलों और नागरिकों की सुरक्षा में मदद की है।

'अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज' (अडानी डिफेंस की 26 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी) और इजराइल की 'एन्लिट सिस्टम्स' की साझेदारी में विकसित स्कार्डैस्ट्राइकर हथियार या कामिकेज ड्रोन 5-10 किलोग्राम के हथियार ले जा सकते हैं, 100 किलोमीटर तक की कम ऊंचाई पर चुपचाप उड़ सकते हैं, और लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकते हैं। अदाणी ने कहा, जैसा कि मेरा हमेशा से मानना है कि हम सुरक्षित क्षेत्रों में काम नहीं करते हैं। हम वहां काम करते हैं, जहां यह जरूरी है, जहां भारत को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है।

अदाणी ने वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम किया। उन्होंने कहा, इस वर्ष 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमारे बहादुर पुरुष और महिलाएं वर्र्दी में डटे रहे। प्रसिद्धि के लिए नहीं, पदकों के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य के लिए। उनके साहस ने हमें याद दिलाया कि शांति कभी मुफ्त नहीं मिलती, इसे अर्जित किया जाता है। और अपने देखने, उन्हें पूरा करने और नेतृत्व करने की स्वतंत्रता हमारी सुरक्षा करने वाले लोगों के कंधों पर मजबूती से टिकी है। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा कि भारत शांति के महत्व को समझता है। उन्होंने कहा, लेकिन अगर कोई उसे खतरे में डालने की कोशिश करता है, तो भारत उसकी भाषा में जवाब देना भी जानता है। अदाणी समूह के चेयरमैन ने कहा कि पश्चिम एशिया में भूराजनीतिक अस्थिरता से लेकर पश्चिम में आर्थिक उथल-पुथल के बावजूद दूरदर्शी नीति निर्माण और साहसिक राष्ट्रीय इरादे के कारण भारत विकास के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरा है।



भारत 'टैरिफ किंग' नहीं, प्रभावी दर बहुत कम : सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इस आरोप को खारिज कर दिया कि भारत 'टैरिफ किंग' (अत्यधिक शुल्क लगाने वाला देश) है। उन्होंने कहा कि उनके ताजा बजट में शुल्क दरों की संख्या घटाकर आठ कर दी गई है और प्रभावी दर बहुत कम है। उन्होंने कहा, जो लोग अब भी अमेरिका में की गई टिप्पणी पर भरोसा करते हैं कि भारत 'टैरिफ किंग' हो सकता है... मैं चाहती हूं कि वे दो बातें याद रखें। हमारी शासन व्यवस्था को देखते हुए हमें शुल्क दर पर निर्णय लेने के लिए

संसद की मंजूरी चाहिए... एक निश्चित स्तर तक जाने की अनुमति, लेकिन प्रभावी रूप से हमारी दरें बहुत निचले स्तर पर हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार भारत को बहुत अधिक शुल्क वाला देश बताया है। ट्रंप ने भारत को 'टैरिफ किंग' और शुल्क व्यवस्था का 'बड़ा दुरुपयोग करने वाला' कहा था।

वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात बढ़ाने के लिए 2025-26 के बजट में शुल्क दरों की संख्या घटाकर आठ कर दी गई।

सीतारमण ने फरवरी के बजट में सात शुल्क दरें हटा दी थीं। यह 2023-24 के बजट में हटाई गई सात शुल्क दरों के अलावा थीं।

सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा को युक्तिसंगत बनाने की योजना को मंजूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के महत्वपूर्ण बाघ आवास (सीटीएच) की सीमा को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव को राज्य वन्यजीव मण्डल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव को अब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के सामने रखा जाएगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस प्रस्ताव में मानवीय गतिविधियों वाले कुछ पहाड़ी इलाकों को अलग करते हुए सीटीएच की सीमाओं को संशोधित करना और होने वाले नुकसान की भरपाई 'बफर जोन' से करना शामिल है। इस प्रस्ताव से इस साल की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बंद कर दी गई, कई संगमरमर और डोलोमाइट खदानों को फायदा होने की संभावना है।

राजस्थान के वन अधिकारी अरिजीत बनर्जी ने कहा, सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीटीएच की सीमा को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव सोमवार को वन्यजीव मंडल की बैठक में रखा गया और इसे पारित कर दिया



गया। हालांकि, उन्होंने उन खदानों की संख्या पर कोई टिप्पणी नहीं की जिन्हें सीमा के युक्तिकरण से लाभ होगा। ये खदानें खोह, पालपुर, तिलवाड़, गोरधनपुरा, मन्नाना, डूंडपुरी, जयसिंहपुरा और कलवार गांवों में और उसके आसपास हैं। प्रस्ताव के अनुसार सीटीएच से बाहर रखे गए इलाकों - मुख्य रूप से मानवीय गतिविधि से प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र - को बाघ अभयारण्य के बफर जोन में जोड़ा जाएगा। ये क्षेत्र अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस

बदलाव से स्थानीय समुदाय और बाघ अभयारण्य प्रबंधन के बीच सीमावर्ती संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

उच्चतम न्यायालय ने बाघ अभयारण्य के अंदर पैदल और निजी वाहनों से लोगों के बेरोक-टोक प्रवेश के मुद्दों के बारे में स्वतः संज्ञान लिया था। 2024 में न्यायालय ने केंद्रीय अधिकारसंपन्न समिति (सीडीसी) को इस मामले पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। जुलाई 2024 में सीडीसी की रिपोर्ट के बाद, राजस्थान सरकार ने इसकी

सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय ने राज्य को एक साल के भीतर युक्तिकरण कार्रवाई पूरा करने का निर्देश दिया। राज्य मंडल में पारित प्रस्ताव अब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (एससी-एनबीडब्ल्यूएल) के समक्ष रखा जाएगा, जिसकी बैठक 26 जून को देहरादून में होने वाली है।

हालांकि वन विभाग के कुछ अधिकारी सीमा के युक्तिकरण का विरोध भी कर रहे हैं। इन्होंने नाम उजागर नहीं किए जाने की शर्त पर कहा कि परिधीय पहाड़ियों को बाहर करने से बाघ अभयारण्य का भीतरी संपर्क एक तरह से टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व की पहाड़ियां अनावश्यक नहीं बल्कि बाघों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान ने 2007-08 में सरिस्का के लिए सीटीएच की सीमा निर्धारित की थी, लेकिन जमीन संबंधी कई विवादों के कारण अधिसूचना लंबित रही। फिलहाल राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव दोनों अलवर का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके चलते विवादास्पद मुद्दों को निपटाने पहल की गई है।



राजस्थान में अनेक जगह भारी बारिश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते बारिश का दौर जारी है और बीते चौबीस घंटे में अनेक जगह भारी से अति भारी बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य में मानसून की सक्रियता अभी बनी रहेगी। इसके अनुसार, मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते चौबीस घंटे में

विशेषकर पूर्वी राजस्थान में कई जगह भारी से अतिभारी बारिश हुई। सबसे अधिक 180 मिलीमीटर बारिश बारां के मांगरोल में दर्ज की गई। इसी तरह बारां में किशनगंज में लगभग 110 ममी. और शाहाबाद में 170 ममी. बारिश हुई। वहीं सर्वाई माधोपुर, दोसा, टोंक, अलवर व झुंझुन जिले में कहीं कहीं 30 से 60 मिलीमीटर तक बारिश हुई।

मौसम विभाग ने आज मंगलवार को भी कोटा, भरतपुर

और जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी या अतिभारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अनुसार पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 25-27 जून के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में आगामी दिनों में एक नया मौसमी तंत्र बनने के कारण पूर्वी राजस्थान में 27 जून से फिर भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी।



शासन सचिव ने भविष्य की कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निर्देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने मंगलवार को मुख्यालय के सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभाग के कार्यों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर भविष्य की कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी जनजीवन से जुड़ी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन

(शहरी), अमृत योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना, शहरों की साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, नालों की सफाई, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं आदि का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नगर निकायों की कार्य क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता एवं जनभागीदारी को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया।

बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख चुनौतियों जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलभराव, स्ट्रीट वेंडर जोन का सुव्यवस्थित संचालन, राजस्व वृद्धि एवं नगरीय निकायों में ई-गवर्नेंस को विस्तार देने की दिशा में अधिकारियों से फीडबैक लिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचना ही विभाग की प्राथमिकता होगी। जैन ने अधिकारियों को कहा कि सभी नगरीय निकाय जनसुनवाई तंत्र को और अधिक संवेदनशील एवं सुदृढ़ बनाएं तथा समयबद्ध सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और पारदर्शिता को आधार बनाकर ही सुशासन की स्थापना संभव है। बैठक में विभाग के निदेशक इंदुराज सिंह, अतिरिक्त निदेशक श्याम सिंह, मुख्य अभियंता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।



देवनानी ने बर्लिन में निर्माणाधीन गणेश मंदिर का किया दौरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में निर्माणाधीन गणेश मंदिर का अवलोकन किया। देवनानी ने इस मंदिर के निर्माण पर प्रसन्नता जाहिर की। उल्लेखनीय है कि देवनानी वर्तमान में जर्मनी प्रयास कर हैं। देवनानी ने मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशी की कामना की। देवनानी ने मंदिर परिसर का अवलोकन कर यहां स्थापित होने वाली मूर्तियां और अन्य निर्माण की जानकारी ली। देवनानी ने मंदिर के ट्रस्टी विल्वनाथन कृष्णामूर्ति से मंदिर निर्माण के बारे में चर्चा की। देवनानी को कृष्णामूर्ति ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। बर्लिन में सनातन परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। यह मंदिर पूजा, विवाह समारोह, गृह प्रवेश और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए स्थान भी उपलब्ध कराएगा। देवनानी को बताया कि यह मंदिर जर्मनी का सबसे बड़ा मंदिर होने का गौरव रखता है। मंदिर का निर्माण सनातन, आध्यात्मिक, पारंपरिक, वैदिक और आगम शास्त्रों के अनुसार किया गया है। यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करता है।

मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने देवनानी को बताया कि मंदिर का निर्माण विल्वनाथन कृष्णामूर्ति के प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने 50 साल पहले बर्लिन में आकर मंदिर बनाने का सपना देखा था। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से जन सहयोग से किया गया है। इसमें किसी भी सरकारी सहायता का उपयोग नहीं किया गया है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए एक

स्थान है बल्कि यह बर्लिन में प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह ऐतिहासिक मंदिर पारंपरिक वैदिक एवं आगम शास्त्रों के अनुसार निर्मित किया जा रहा है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए एक पवित्र स्थल है बल्कि यह जर्मनी में बसे भारतीय एवं विशेष रूप से तमिल मूल के लोगों के लिए एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया है।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को जर्मनी प्रवास के दौरान बर्लिन में महापौर के कार्यालय एवं जर्मन स्टेट असेंबली का अवलोकन किया। बर्लिन महापौर को वहां रेजीडेंडर बर्गोमास्टर कहा जाता है। देवनानी को बर्लिन मेयर ने बताया कि बर्लिन की स्टेट असेंबली का भवन न केवल बर्लिन की प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक है अपितु आधुनिक लोकतंत्र की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली का जीवंत उदाहरण भी है। इस अवसर पर देवनानी ने बर्लिन की कार्यकारी सभे के प्रशासनिक तंत्र और जनहित नीतियों के क्रियान्वयन मॉडल को संगठित लोकतंत्र की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति बताया। देवनानी ने कहा बर्लिन जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर का प्रशासनिक मॉडल यह दर्शाता है कि तकनीक, नागरिक सहभागिता और पारदर्शिता के साथ एक शहर किस प्रकार भविष्य की दिशा तय कर सकता है। राजस्थान विधानसभा के लिए यह अनुभव अत्यंत प्रेरणादायी है। इस ऐतिहासिक दौरे के माध्यम से न केवल प्रशासनिक अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ बल्कि दो प्राचीन सभ्यताओं भारत और जर्मनी के मध्य लोकतांत्रिक मूल्यों की साझी चेतना और संवाद की भूमि भी सशक्त हुई।

उदयपुर में फ्रांसीसी पर्यटक से दुष्कर्म का मामला, आरोपी फरार

जयपुर। उदयपुर शहर में फ्रांस की एक पर्यटक के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपी फरार है। आरोप है कि व्यक्ति इस पर्यटक को एक पार्टी से बहला-फुसलाकर अपने किराए के अपार्टमेंट में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अनुसार घटना सोमवार को बड़गांव थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बताया कि 22 जून को दिल्ली से उदयपुर पहुंची महिला अंबामाता क्षेत्र के एक होटल में ठहरी थी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है और उसके बयान के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी फरार है। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि पीड़िता आरोपी के संपर्क में कैसे आई, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। थानाधिकारी पूर्ण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि महिला टाइगर हिल स्थित 'द ग्रीक फार्म कैफे एंड रेस्तरां' में एक पार्टी में गई थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी सिद्धार्थ से हुई। उन्होंने बताया, आरोपी ने महिला को आसपास की जगहें दिखाते के बहाने बाहर बुलाया और बाद में उसे सुखेरे में अपने किराये के अपार्टमेंट में ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि महिला की हानत स्थिर बताई जा रही है और उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राथमिकी के अनुसार, महिला ने बार-बार होटल लौटने की मिन्नत की लेकिन लेकिन आरोपी ने मना कर दिया।

सीमाई क्षेत्र में संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

जैसलमेर। राजस्थान में जैसलमेर के सीमाजन कल्याण समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भेटकर जिले में चल रहे जासूसी नेटवर्क एवं यहां कार्यरत कंपनियों और नहरी मुख्यों पर बाहरी संदिग्ध व्यक्तियों के आगमन पर चिंता जाहिर करते हुए उन्हें बाहर निकालने के लिए अभियान चलाने की मांग की है।

समिति के जिला मंत्री भूरसिंह बीदा ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि सीमावर्ती जैसलमेर जिले में कार्यरत कंपनियों एवं नहरी मुख्यों पर बाहरी संदिग्ध लोग बिना जांच पड़ताल के प्रवेश कर रहे हैं। कई संदेहास्पद लोग तो प्रतिबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उन्होंने उनकी शिनाख्त करके कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जैसलमेर जिले में जासूसी का नेटवर्क काम कर रहा है। पुलिस और जांच एजेंसियों की तत्परता से अक्टूबर तक की समयावधि निर्धारित कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त अवधि में शत प्रतिशत पैक्स की आमसभा अतिवाय रूप से सम्पन्न हो। साथ ही, पैक्स के सूचना पटल में वर्णित जमाओं व अन्य संबंधित जानकारीयों के विवरण के साथ आमसभा के फोटो भी मंगाए जाएं। इससे सहकारी समितियों के कामकाज में



जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की संवेदनशीलता और त्वरित पहल का निकला सफल परिणाम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले झालावाड़ और बारां जिलों के 27 ग्रामों के शेष मकानों के लिए 36.97 करोड़ रुपये की विशेष अनुदान राशि स्वीकृत हुई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की संवेदनशीलता और त्वरित पहल से वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है। अब शीघ्र ही प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि उपलब्ध हो सकेगी।

परियोजना के तहत पहले से ही झालावाड़ और बारां के 47 ग्रामों की डूब प्रभावित भूमि और 29 ग्रामों के आंशिक व पूर्ण डूब प्रभावित मकानों के लिए मुआवजा दिया जा रहा है। हालांकि, इस दौरान राजकीय भूमि (चारागाह, सिंवायचक्र, वन भूमि) पर बने मकानों को मुआवजे के लिए शामिल नहीं किया था। इनमें झालावाड़ की तहसील खानपुर और अकलेरा के 17 तथा बारां की तहसील छीपाबड़ौद के 10 गांव शामिल हैं। अब इनके 1090 मकानों के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री ने 22

और 23 अप्रैल, 2025 को परवन बांध निरीक्षण के दौरान प्रभावितों से मुलाकात कर समस्या को गंभीरता से सुना। इसके बाद रावत ने विभागीय अधिकारियों को राजकीय भूमि पर स्थित मकानों परिसम्पत्तियों के लिए विशेष राशि के रूप में मुआवजे का प्रस्ताव तैयार राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए थे।

रावत की संवेदनशीलता और त्वरित पहल का ही परिणाम रहा कि वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त हुई है। मुआवजा राशि मिलने से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। साथ ही, परवन

परियोजना के शेष निर्माण कार्यों में भी गति आएगी। उल्लेखनीय है कि परियोजना में 571 ग्रामों की 2.0 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। साथ ही, 1402 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि 'हाड़ौती के लिए महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी परियोजना के डूब क्षेत्र के प्रभावितों को न्याय और सम्मानजनक मुआवजा मिलेगा। इससे परियोजना के कार्यों में तेजी आएगी और निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सकेगा।

‘सहकार से समृद्धि’ के अंतर्गत किए जा रहे नवाचारों में लाएं गति : दक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी समितियों में ऑडिट और आमसभा की कार्यवाही समयबद्ध रूप से सम्पन्न होनी चाहिए। आमसभा केवल औपचारिकता नहीं हो, बल्कि इसमें लोगों को सुझाव प्राप्त करने और नवाचारों की जानकारी देने पर फोकस किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को अभियान चलाकर पैक्स स्तर तक खाद-बीज की गुणवत्ता की जांच करने तथा विभाग में मॉनिटरिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

दक मंगलवार को शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित अपने कक्ष में 'सहकार से समृद्धि' के अंतर्गत किए जा रहे नवाचारों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आमसभा आयोजित करने के लिए 1 से 7 अक्टूबर तक की समयावधि निर्धारित कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त अवधि में शत प्रतिशत पैक्स की आमसभा अतिवाय रूप से सम्पन्न हो। साथ ही, पैक्स के सूचना पटल में वर्णित जमाओं व अन्य संबंधित जानकारीयों के विवरण के साथ आमसभा के फोटो भी मंगाए जाएं। इससे सहकारी समितियों के कामकाज में



पारदर्शिता आएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास खाद-बीज विक्रय के लाइसेंस हैं, उनका आगामी दिनों में अभियान चलाकर आवश्यक रूप से निरीक्षण करवाया जाए। निरीक्षण के दौरान खाद-बीज की गुणवत्ता की जांच कर सुनिश्चित किया जाए कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

सहकारिता मंत्री ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में और गति लाने तथा गो-लाइव हो चुकी पैक्स को हैण्ड-होल्डिंग सर्टिफिकेट यथाशीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गो-लाइव हो चुकी पैक्स की ई-ऑडिट करवाई जाए। बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया कि अब तक 5,301 पैक्स गो-लाइव हो चुकी है जबकि, 2,398 पैक्स को हैण्ड होल्डिंग प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि

अब तक 713 पैक्स द्वारा ई-ऑडिट करवाई जा चुकी है। दक ने बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों के गठन में अपेक्षित प्रगति हासिल करते हुए एनसीडी पोर्टल पर डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में पैक्स के गठन तथा निष्क्रिय सहकारी समितियों के अवसायन के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

दक ने विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे गोदामों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने तथा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप इन्हें किराये पर देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इससे पैक्स की आय में वृद्धि होगी। दक ने कहा कि पैक्स द्वारा जन औषधि केन्द्र का संचालन करने से पूर्व उसकी व्यवहार्यता परखी जाए।

उन्होंने कहा कि पैक्स द्वारा एफपीओ के साथ ही नये कर्टम हायरिंग सेंटर खोले जाने की दिशा में भी कार्य किया जाए। इससे उनकी अतिरिक्त आय हो सकेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

उन्होंने नये गठित होने वाले पैक्स के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता अनिवार्य किए जाने पर भी जोर दिया। प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवहार्यता के अनुसार भारत सरकार से डेयरी सहकारी समितियों के लक्ष्य में संशोधन का आग्रह किया जा सकता है।



प्रेम के मायने वही समझ सकता है जिसने राधा के दिल की धड़कनों में कृष्ण की धुन सुनी हो।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

युवा शक्ति और उज्ज्वल भविष्य

होसपेट के एमजे नगर में युवाओं के लिए आयोजित सेमिनार में आचार्यश्री विमलसागरसूरी ने जो प्रवचन दिए, वे समाज और राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। उनके ये शब्द अत्यंत प्रासंगिक हैं कि 'देश का भविष्य व्यापार-उद्योग, सेना, प्रशासन, जीडीपी की वृद्धि और साधन-सुविधाओं के भरोसे ही उज्ज्वल होगा, ऐसा नहीं है। देश के किशोर और युवा कौनसी राह पर आगे बढ़ते हैं, उस पर भविष्य निर्भर करेगा। किशोर तथा युवा वर्ग राष्ट्र और समाज की रीढ़ हैं।' यह संदेश आज के भौतिकवादी युग में एक गहरी चेतना जगाता है। आज का दौर उपभोग और तात्कालिक सुख की ओर झुका हुआ है। सोशल मीडिया, मनोरंजन और भौतिक सुखों की दौड़ में अच्छाइयों और नैतिक मूल्यों का स्थान धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है। मनुष्य को बुराइयों जल्दी प्रभावित कर रही हैं। अच्छाइयों को अपनाने के लिए तो आत्म-नियंत्रण और सतत प्रयासों की आवश्यकता होती है। यह एक कठु सत्य है कि आज बुराइयों का प्रचार-प्रसार अधिक हो रहा है और यह समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। युवा वर्ग, जो ऊर्जा, उत्साह और नवाचार का प्रतीक है, उसे इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। प्रश्न है- अच्छाई को कैसे बढ़ावा दिया जाए? लोग यह तो शिकायत करते हैं कि बुराइयां बढ़ गई हैं। अखबार, टीवी, सिनेमा, सोशल मीडिया ... जहां नजर जाती है, ये ही ज्यादा दिखती हैं। उनका कहना गलत भी नहीं है। अब इसके दूसरे पहलू को देखें। बेशक बुराइयां बढ़ रही हैं, लेकिन अच्छाइयों को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जब ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छाई के समर्थन में खड़े होंगे, तब ही तो उसकी जड़ मजबूत होगी। अच्छे साहित्य और अच्छे सिनेमा की कमी इसलिए है, क्योंकि उन्हें बहुत कम लोगों का समर्थन मिलता है। जिस दिन लोग अच्छाई को बढ़ावा देने में रुचि लेने लगेंगे, उसका पलड़ा अपनेआप भारी हो जाएगा।

आचार्यश्री का यह कथन कि 'अच्छाइयों को जीवित रखने के लिए समाज के संगठित प्रयास जरूरी हैं', हमें सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। केवल धन कमाने या उत्सवों में डूबे रहने से न तो व्यक्ति का कल्याण संभव है और न ही समाज का भला हो सकता है। युवाओं को धर्म, नैतिकता और मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूक करना आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या हम अपने युवाओं को सही दिशा दे पा रहे हैं? हम उन्हें केवल कमाई और भौतिक सफलता की दौड़ में धकेल रहे हैं या उन्हें एक संतुलित, मूल्य-आधारित जीवन जीने की प्रेरणा भी दे रहे हैं? आचार्यश्री का संदेश स्पष्ट है- युवा वर्ग को न केवल आर्थिक और सामाजिक प्रगति का वाहक बनाना है, बल्कि उसे ऐसी पीढ़ी के रूप में ढालना है, जो अच्छाइयों को संजोए और बुराइयों का डटकर मुकाबला करे। इसके लिए परिवार, समाज और शिक्षण संस्थानों को मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा, जहां युवा न केवल तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करें, बल्कि नैतिकता, करुणा और आत्म-अनुशासन जैसे गुण भी विकसित करें। आचार्यश्री के प्रवचन हमें यह स्मरण कराते हैं कि राष्ट्र का भविष्य केवल धन-दौलत से उज्ज्वल नहीं हो सकता। भावी पीढ़ी को चरित्रवान भी बनाना होगा। यह संदेश किसी एक समुदाय या वर्ग के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र एवं मानवता के लिए है। यह हर उस व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए प्रासंगिक है, जो एक बेहतर, मूल्य-आधारित और समृद्ध भविष्य की कामना करता है। इस समय अपने युवाओं को वह शक्ति देनी होगी, जो उन्हें न केवल स्वयं का, बल्कि पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में सक्षम बनाए।

ट्वीटर टॉक



जादूगरी केवल मनोरंजन नहीं, एक प्राचीन और आकर्षक कला है जो पीढ़ियों से लोगों को आश्चर्यचकित करती आ रही है। आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में प्रसिद्ध जादूगर श्री ओपी शर्मा का शो देखा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी मंत्रमुग्ध नजर आए।

-अशोक गहलोत

मुंबई में आयोजित संसद तथा राज्यो/संघ क्षेत्रों के विधान मंडलों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। प्राक्कलन समितियों के सभापतियों का यह सम्मेलन वित्तीय अनुशासन और संस्थागत समन्वय के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

-ओम बिरला



राजस्थान की गवीली विरासत को अपने अद्भुत स्थापत्य और संस्कृति से दर्शाने वाली महाधरा बूंदी के 784वें स्थापना दिवस की सभी बूंदीवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ! ईश्वर की कृपा इस महान नगर पर सदैव विद्यमान रहे।

-गजेन्द्र सिंह शेखावत

प्रेरक प्रसंग

तेजवान की कसौटी

अंगिरा ऋषि का शिष्य उदयन अत्यंत तेजस्वी सरल तथा सेवाभावी वृत्ति का था। गुरु ने देखा कि कुछ दिनों से वह आलस्य व अहंकार का शिकार होता जा रहा है। एक दिन ऋषि ने उदयन से कहा, 'वत्स, सामने रखी अंगीठी में झांक कर देखो, कोयला दहकने के कारण कितना तेजवान लग रहा है। इसे चिमटे से निकालकर मेरे सामने रख दो जिससे इसकी तेजस्विता का पास से अवलोकन कर सकूँ।' उदयन ने चिमटे से कोयला उठाया और गुरुदेव के पास रख दिया। कुछ ही क्षणों में कोयला अंगारे की जगह राख में बदल गया।

ऋषि ने उदयन को समझाया, 'वत्स, अंगीठी का सबसे चमकदार कोयला जिस प्रकार अग्नि के तेज से विमुख होते ही राख बन गया उसी प्रकार सक्रिय और प्रतिभावान व्यक्ति अभ्यास, स्वाध्याय तथा सक्रियता से विमुख होते ही आलस्य तथा अहंकार का शिकार होकर निरतेज हो जाता है।' उदयन गुरु जी का आशय समझ गया तथा उन्होंने अहंकार और आलस्य त्याग कर पुनः कर्मठ जीवन बिताना शुरू कर दिया।

अशोक भाटिया

मोबाइल : 9221232130

पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भले नजर न आते हों, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनको शिद्धत से महसूस किया जाता है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुकाबले पंजाब व गुजरात में कहीं ज्यादा देखा जा रहा था - और वो अकेले नहीं बल्कि मनीष सिंसोदिया सहित उनकी भरोसेमंद पूरी टीम भी वहीं डटी हुई थी। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल निकले तो थे विपक्षना के लिए, लेकिन उसके बाद भी पंजाब व गुजरात में ही जमे हुए हैं। पंजाब में रुकने की बड़ी वजह तो वहां आम आदमी पार्टी की सरकार होना है, जिसे जैसे भी संभव हो बचाकर रखना अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता की राजनीति कितना मायने रखती है, पंजाब व गुजरात अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की मौजूदगी सबसे बड़ी मिसाल रही।

यही कारण है कि गुजरात में दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए उत्साही संकेत लेकर आए हैं। विसावरद सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने भाजपा के किरिट पटेल को करीब 17,554 वोटों से हराया है। भाजपा को यह हार बहुत चुभेगी, क्योंकि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के होम्सग्रउंड में आप के बहानों करारी शिकस्त मिली है। इसके अलावा, यह राष्ट्रवाद और अपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों के ऊपर क्षेत्रीय समस्याओं और आकांक्षाओं की जीत का भी संकेत है। दरअसल इस सीट पर पहले भी आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन विधायक भूपेन्द्रभाई गांडुभाई भायाणी पार्टी बदलकर भाजपा में शामिल हो गए थे। इस वजह से उपचुनाव कराए गए थे। भाजपा को जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। विसावरद विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी आप के गोपाल इटालिया ने भाजपा के किरिट पटेल को 17,554 वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भाजपा को इस सीट पर आखिरी बार 2007 में जीत मिली थी और तब से इस सीट पर जीत के लिए पार्टी तैरस रही है। इस बार यहां जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। आम आदमी पार्टी की सटीक रणनीति और सही उम्मीदवार के चुनाव की वजह से भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। विसावरद सीट पर लगातार दूसरी बार आप की झाड़ चली है। आम आदमी पार्टी की दोबारा इस सीटें पर जीत प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के गुजरात मॉडल को चुनौती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली

सामयिक

गुजरात उपचुनाव की सीट हारने को गंभीरता से ले भाजपा

विसावरद की जीत आप के लिए सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। दिल्ली में 2024 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद आप को एक मजबूत वापसी की जरूरत थी। विसावरद और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर मिली जीत ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है। आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरव भारद्वाज ने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप खतम हो गई है लेकिन यह जीत दिखाती है कि जनता हमारे साथ है। यह केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में शानदार वापसी है।

हार के बाद पार्टी ने यहां बेहतरीन उपस्थिति दर्ज कराई है। इस जीत ने साबित कर दिया है कि सही उम्मीदवार और जनता के मुद्दे उठाने का असर चुनावी नतीजों पर नजर आता है। इतना ही नहीं यह इस बात का भी संकेत है कि जनता विकल्प को अपनाने में नहीं हिचक रही है। गुजरात का रिजल्ट भाजपा के लिए भी एक करारा झटका है। जो दशकों से गुजरात में अजेय मानी जाती रही है। इस जीत ने न सिर्फ आप की साख को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि यह भी साबित किया कि गुजरात की जनता अब बदलाव की ओर कदम बढ़ा रही है। दरअसल विसावरद जूनागढ़ जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। जो लंबे समय तक भाजपा का गढ़ रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री केशूभाई पटेल जैसे दिग्गज नेताओं ने इस सीट पर भाजपा का परचम लहराया था। हालांकि 2007 के बाद से भाजपा इस सीट पर जीत का स्वाद नहीं चख पाई थी। गोपाल इटालिया ने न केवल इस सीट को वापस हासिल किया। बल्कि भाजपा को उसकी ही जमीन पर चारों खाने चित कर दिया।

गौरतलब है कि गुजरात में भाजपा की सरकार पिछले दो दशकों से सत्ता में है। इस दौरान विकास के बड़े-बड़े दावे किए गए। लेकिन ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों की कमी आज भी देखी जा सकती है। विसावरद जैसे कृषि-प्रधान क्षेत्र में किसानों की समस्याएं सिंचाई की कमी, फसलों का उचित मूल्य न मिलना। और कर्ज का बोझ भाजपा के लिए मुसीबत बन गई। गोपाल इटालिया ने इन मुद्दों को जोर-शोर से उठाया। और जनता के बीच यह संदेश देने में कामयाब रहे कि आप उनकी आवाज बन सकती है। गोपाल इटालिया पहले आप के गुजरात अध्यक्ष रह चुके हैं। एक जमीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी सादगी, बेबाकी और जनता से सीधा संवाद उनकी जीत का सबसे बड़ा हथियार बना। और उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार, तानाशाही और जनविरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। इसके अलावा आप ने दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकारों के काम मुफ्त बिजली, बेहतर स्कूल और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को गुजरात की जनता के सामने

मॉडल के तौर पर पेश किया। यह रणनीति विसावरद के मतदाताओं, खासकर युवाओं और किसानों के बीच खूब जमी।

वहीं भाजपा के लिए यह हार सिर्फ बाहरी कारणों की वजह से नहीं। बल्कि पार्टी के भीतर की गुटबाजी और नेतृत्व की कमजोरियों ने भी इस हार को और गहरा किया। किरीट पटेल को टिकट देने के फैसले पर स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। इसके अलावा भूपेंद्र भायानी के आप छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने जिस तरह से उन्हें बढ़ावा दिया। उससे विसावरद की जनता में गुस्सा था। लोगों ने इसे 'दलबदल की राजनीति' के तौर पर देखा और भाजपा को सबक सिखाने का मन बना लिया था कांग्रेस कभी गुजरात में भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी थी। अब पूरी तरह से हाशिए पर चली गई है। विसावरद में नितिन रणपरिया की हार और महज 5,501 वोट मिलना कांग्रेस की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। कांग्रेस की कमजोरी का फायदा सीधे तौर पर आप को मिला क्योंकि जो वोटर भाजपा के खिलाफ थे और उन्होंने आप को एक मजबूत विकल्प के तौर पर चुना। गोपाल इटालिया की यह जीत उनकी मेहनत और आप की रणनीति का नतीजा है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले गोपाल ने अपनी बेबाकी और जमीनी मुद्दों पर पकड़ के दम पर विसावरद की जनता का दिल जीता। और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए जैसे कि भाजपा उम्मीदवार द्वारा शराब बांटने की कोशिश। आप ने इस मामले को सोशल मीडिया पर खूब उछाला जिससे भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा। विसावरद की इस जीत ने गुजरात की सियासत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भाजपा का अजेय किला अब कमजोर पड़ रहा है ? क्या आप गुजरात में कांग्रेस की जगह लेने जा रही है ? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में आप भाजपा के लिए एक मजबूत चुनौती पेश कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब तो वक्त देगा। लेकिन यह जीत निश्चित तौर पर 'आप' के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कदम है।

वहीं 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में भाजपा के पास 161 सीटें थीं। जो अब 162 हो गई हैं। क्योंकि उन्होंने कड़ी सीट पर जीत

हासिल की। लेकिन विसावरद की हार भाजपा के लिए एक चेतावनी है। अगर आप इसी तरह जमीनी स्तर पर काम करती रही तो 2027 में भाजपा के लिए चुनौती बढ़ सकती है। भाजपा को अब अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। विसावरद की हार के बाद भाजपा के लिए कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या पार्टी ने सही उम्मीदवार चुना। क्या स्थानीय मुद्दों को समझने में चूक हुई। क्या दलबदल की राजनीति अब उल्टा पड़ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने हार के बाद कहा कि वे इस पर आत्ममंथन करेंगे लेकिन यह साफ है कि पार्टी को अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। आपको बता दें कि भूपेंद्र भायानी का आप से भाजपा में जाना और फिर किरीट पटेल को टिकट देना भाजपा के लिए भारी पड़ गया। जनता ने इसे दलबदल की राजनीति के तौर पर देखा। और इसका जवाब वोट के जरिए दिया। यह भाजपा के लिए एक सबक है कि दलबदल कराने की रणनीति हमेशा कामयाब नहीं होती।

भाजपा का प्रचार इस बार उतना प्रभावी नहीं रहा जितना पहले देखा गया था। गोपाल इटालिया ने जमीनी स्तर पर घर-घर जाकर प्रचार किया जबकि भाजपा का प्रचार मुख्य रूप से अपनी सरकार के दावों तक सीमित रहा इसके अलावा आप ने सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया खासकर शराब बांटने के आरोप को वायरल करके।

विसावरद की जीत आप के लिए सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। दिल्ली में 2024 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद आप को एक मजबूत वापसी की जरूरत थी। विसावरद और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर मिली जीत ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है। आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरव भारद्वाज ने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप खतम हो गई है लेकिन यह जीत दिखाती है कि जनता हमारे साथ है। यह केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में शानदार वापसी है। वहीं यह जीत आप के लिए 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकती है अगर आप इसी तरह जमीनी स्तर पर काम करती रही तो यह गुजरात में भाजपा के लिए एक मजबूत चुनौती बन सकती है। बता दें कि गोपाल इटालिया की विसावरद में जीत न केवल आप की ताकत को दर्शाती है। बल्कि यह भी बताती है कि गुजरात की जनता अब बदलाव के मूड में है। भाजपा के लिए यह हार एक चेतावनी है कि उनकी जमीन अब खिसक रही है। अगर पार्टी ने समय रहते अपनी रणनीति में सुधार नहीं किया तो 2027 के चुनाव में उसे और बड़े झटके लग सकते हैं दूसरी ओर आप और गोपाल इटालिया के लिए यह जीत एक नई शुरुआत है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आप इस जीत को गुजरात में एक बड़े सियासी बदलाव में बदल पाएंगी।

नजरिया

आपातकाल : आधी रात जब छिन गए थे जनता के सारे अधिकार

डॉ. आशीष वशिष्ठ

मोबाइल : 94-5100-5200

पचास वर्ष पूर्व आज के दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। पूरा देश इस फैसले से भौंचक रह गया। भारतीय इतिहास में लोकतंत्र का काला दिन था। आपातकाल लगाया गया, जो मार्च 1977 तक चला। इस दौरान भारत में लोकतंत्र लगभग खत्म कर दिया गया और एक तानाशाही शासन की शुरुआत इस दौरान नागरिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया, मीडिया की आजादी छीन ली, लोगों के मौलिक अधिकारों को रौंदा, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और आम नागरिकों को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और हत्या तक की गई। इस दौर में संविधान को भी कमजोर किया गया। हालांकि, आपातकाल का हर पहलू चॉकाने वाला था, लेकिन खासकर छात्रों पर किए गए अत्याचार बेहद निंदनीय थे। सब कुछ सिर्फ एक परिवार की तानाशाही को बरकरार रखने के लिए।

पहली बार ऐसा मौका था जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी। लोगों को आपातकाल के मतलब भी नहीं था था। आपातकाल की घोषणा के साथ ही आम जनता के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। किसी तरह की अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। आम जनता, मीडिया समूह, रेडियो, और अन्य प्रचार के माध्यमों पर पूरी पाबंदी लगा दी गई थी। आपातकाल की घोषणा के कुछ घंटे के भीतर की प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों में बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी। आपातकाल की सूचना के बाद से ही देश में दूढ़-दूढ़ कर विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां का दौर शुरू हो गया था। तत्कालीन समय के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में डाल दिया गया। विपक्षी नेताओं के साथ साथ समाज में प्रभाव रखने वाले कांग्रेस के विपरीत विचारधारा वाले सभी लोगों और आम जनता में बेगुनाहों को भी जेल में भर दिया गया था, जेलों में जगह नहीं



बची थी। करीब 1,40,000 लोगों आपातकाल में बिना किसी सुनवाई के राजनीतिक बंदी बनाया गया।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपातकाल के दौरान पूरे देश का नियंत्रण गांधी-नेहरु परिवार के हाथ में था। कांग्रेस ने आपातकाल की आड़ में वो सभी काम किए जो ना सिर्फ राजनीतिक लिहाज से अशोभनीय थे बल्कि अमानवीय भी थे। प्रेस में सरकार या आपातकाल की आलोचना करना अपराध की श्रेणी में आ चुका था। प्रेस-मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी तैनात किया गया था। हालात यह थे कि कांग्रेस समर्थित उस अधिकारी के अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तारी हो रही थी। यही नहीं, कांग्रेस का विरोध करने वाले 26 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय विचार और भारतीयता के लिए काम करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल के मुखर आलोचक रहे फिल्मी कलाकारों को भी इसका दंश झेलना पड़ा। किशोर कुमार के गानों को रेडियो और दूरदर्शन पर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देव आनंद को भी अनौपचारिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था।

देश में आपातकाल लागू होने के बाद कई त्रासद घटनाएं हुईं। दिल्ली का तुर्कमान गेट कांड भी इनमें एक था। मुस्लिम बहुल कस इलाके को संजय गांधी ने दिल्ली के सौंदर्यकरण के नाम पर खाली करा दिया। यह काम लोगों की सहमति से

नहीं, बल्कि जबरन किया गया गया। बुल्डोजर से लोगों के घर ढहाए गए। जिन्होंने विरोध किया, उन्हें जेलों में दूंस दिया गया। विरोध के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज बरसाई और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने गोलियां भी चलाईं। चार लोगों की जान चली गई।

संजय गांधी की सनक के चलते सड़क से भिखारियों, झोड़पड़ी के लोगों और राहगीरों को पकड़ कर जबरन नसबंदी के टार्गेट पूरे किए जाने लगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 18 अक्टूबर 1976 को नसबंदी अभियान का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने सीधी फायरिंग कर दी थी। जिसमें 42 बेगुनाहों की मौत हो गई थी। मृतकों की स्मृति में यहां शहीद चौक बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान देशभर में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। 21 महीने के बाद जयप्रकाश का आंदोलन निर्णायक मुकाम तक जा पहुंचा। इंदिरा गांधी को सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की सरकार ने 28 मई 1977 में आपातकाल के दौरान हुए ज्यादतियों को जानने के लिए जस्टिस जे सी शाह की अध्यक्षता में शाह कमीशन गठित किया। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि जिस वक्त आपातकाल की घोषणा की गई उस वक्त ना देश में आर्थिक हालात खराब थे और ना ही कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोई अड़चन थी। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल अपनी इच्छा के अनुसार लगाया था और इस संबंध में उन्होंने अपने पार्टी के कुछ लोगों को छोड़कर किसी भी सहयोगी से कोई विमर्श नहीं किया था।

आपातकाल में गिरफ्तार किए गए अधिकतर सम्मानित और बुजुर्ग नेताओं को भिकित्सा सुविधा की आवश्यकता थी, जो उन्हें अस्पताल में मौजूद नहीं कराई गई। इंदिरा गांधी की तानाशाही का एक नमूना इस बात से भी पता चलता है कि शाह आयोग ने नसबंदी कार्यक्रम पर सरकार के रवैए की बेहद आलोचना की थी। आयोग ने कहा था कि पटरी पर रहने वाले और भिखारियों की जबरदस्ती नसबंदी की गई इसके साथ-आंटी रिक्शा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए नसबंदी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया था। आयोग ने यह स्पष्ट रूप से माना था कि सरकारी तंत्र का उपयोग कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस पूरे आपातकाल का इस्तेमाल किया गया।

जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया कि वर्ष 1975 में आपातकाल के समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल नीरेन डे ने तब सुप्रीम कोर्ट में यह कबूल किया था कि जीने का अधिकार स्थगित है। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्थिति को लेकर एक श्वेत पत्र 1 अगस्त 1977 में संसद में पेश किया गया। सत्या सी पेज के श्वेत पत्र से यह स्पष्ट हुआ कि तानाशाही की इच्छा रखने वाली इंदिरा गांधी ने अपनी अध्यक्षता में तय किया था कि प्रेस काउंसिल को भंग कर दिया जाए और तत्कालीन चारों समाचार एजेंसियों को मिलाकर एक कर दिया जाए, जिससे उन्हें सेंसर करने और संभालने में आसानी होगी।

राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता पिछले कुछ समय अक्सर लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। संसद से सड़क तक वे संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि उनकी पार्टी के नेता ने दादागिरी करके इस देश पर 21 महीने आपातकाल लगाकर लोगों को जेल में दूंस दिया था। असल में, 1975 में लगाया हुआ आपातकाल इंदिरा गांधी की गलती नहीं थी, बल्कि इंदिरा गांधी का अहंकार था। दिसंबर 2024 को सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का उल्लेख किया और कहा, दुनिया में जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कांग्रेस के माथे से कभी यह कलंक मिट नहीं सकेगा क्योंकि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। भारतीय संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी।

महत्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kannami Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor: Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor- Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No.: TNMH / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (बैंगलिक, वर्गीकृत, टेंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वर स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादकों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा वादा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरवाई नहीं करा सकता। - दक्षिण भारत राष्ट्रमत

